# भारत में बेरोजगारी का विकल्प : स्वरोजगार योजनाएँ

डॉ. आनंद तिवारी
विभागाध्यक्ष वाणिज्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर

**सारांश -**

*समूची दुनिया में भारत आज अग्रणी राष्ट्रों में गिना जा रहा है। निसंदेह एवं निर्विवाद रूप से चाहे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें चाहे भौतिक संसाधनों की विश्व मानचित्र पर स्वयं को रेखांकित कर लिया है। यहां यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि आज भारत में मानवीय संसाधनों के समुचित समायोजन हेतु शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वे सराहनीय है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आज भारतीय युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास की दिशा में प्रेरित किया जाये।*

**मुख्य शब्द** - स्वरोजगार, समायोजन, संसाधन, जनतांत्रिक, सर्वांगीण समन्वित, समावेशित

**शोध परिकल्पनायें -**

1. भारत प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधन की दृष्टि से विश्व में सम्पन्न राष्ट्र है।
2. भारत की ज्वलंत समस्याओं में महती समस्या बेरोजगारी है।
3. भारत युवा आबादी का देश है, 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 20-35 वर्ष आयु वर्ग की है। आवश्यकता इस मानवीय संसाधन के समुचित समायोजन की है।
4. आबादी के इतने बढ़े भाग का समायोजन सरकारी, गैर-सरकारी नहीं हो सकता है। आवश्यकता है कि रोजगार हेतु स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाये।
5. शासन स्तर पर वर्तमान में की जा रही योजनाओं से निश्चित रूप से ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर रोजगार की स्थिति में बदलाव आया है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि कौशल विकास जैसे कार्यक्रम त्वरित गति से लागू किए जायें।

**शोध समस्या का चयन -**

भारत समूची दुनिया का सबसे विशाल एवं सफल लोकतंत्र कहलाता है। विशाल इसलिए क्योंकि जनांकिकीय दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर 135 करोड़ की आबादी वाला देश है जिसमें 65 प्रतिशत युवा आबादी है जिसकी आयु 25-35 वर्ष की है। यह आबादी हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बुनियाद है। भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जल जंगल और जमीन जैसी संपदाओं से सम्पन्न है।

दुनिया के कतिपय राष्ट्र स्वयं को जनतांत्रिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। परन्तु कतिपय

ऐसे राष्ट्र है जहां जनप्रतिनिधियों का चयन हेतु केवल एक दल, एक विचारधारा और एक पार्टी का होता है या तो उसे स्वीकार करना होता है अथवा अस्वीकार। उनसे कोई विकल्प ही नहीं होता। ऐसे राष्ट्रों में कई बार अस्वीकार करने वाले पर समुचित कार्यवाही की जाती है और कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं। जहां जनप्रतिनिधियों का चयन कुलीन वर्ग एवं शासक वर्ग से करना होता है। इन देशों को लोकतांत्रिक राह करना कहां तक उचित होगा। जब भारतीय संदर्भ में हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सच्चे अर्थो में भारत लोकतंत्र को परिभाषित करता है। जहां जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन होता है जनता का आशय, शहरी एवं ग्रामीण, पुरुष एवं महिला, साक्षर एवं निरक्षर जनमानस है जो किसी भी धर्म, भाषा एवं सम्प्रदाय की हो शामिल होती है। यही कारण है भारत में सही अर्थो में लोकतंत्र स्थापित है।

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का एक अन्य कारण यह भी है कि जब हम कहते है कि भारत को कौन चला रहा है तो हमारा सीधा और सपाट उत्तर होता है, प्रशासन (अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य अखिल भारतीय शहर की सेवाओं में पदस्थ नौकरशाह) ही देश को चला रहे हैं परन्तु प्रशासन शासन के अधीन (अर्थात सांसद, विधायक जनप्रतिनिधि) कार्यरत होते है और शासन से की संनिष्ठा संविधान के प्रति होती हैं तो इस आधार पर संविधान लोकतंत्र में सबसे ऊंचे पैमाने पर माना जाना चाहिए परन्तु संविधान से ऊपर यदि कोई है तो वह 18 वर्ष से अधिक आयु का युवा जिम्मेदार नागरिक है।

इस आधार पर लोकतंत्र में सर्वोपरि यदि कोई है तो वह है 'युवा' तरुण है जिसकी जिज्ञासायें हैं, जो लोकतंत्र का भविष्य है जो मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और मानव संसाधन के ऐसे उपकरण को विकास हेतु तीन आयाम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण माने जाते है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार। किसी भी नागरिक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और नागरिक का भी शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार भी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना भी संवैधानिक दायित्व माना गया है।

## अध्ययन एवं विश्लेषण -

भारत के सर्वांगीण समन्वित एवं एकीकृत एवं समावेशित विकास हेतु यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि रोजगार की स्थिति का मापन न केवल मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर किया जाये। अपितु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के समुचित सामायोजन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी संसाधन एवं संस्थागत ढांचे जैसे बुनियादी पहलू पर विचार किया जावे। देश में लगभग 12 करोड़ युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। यह कुल आवादी का 11 प्रतिशत है इसमें भी 50 प्रतिशत ऐसे युवा हैं जो पूर्णतया बेरोजगार है शेष के पास आर्थिक रोजगार उपलब्ध है। 20 वर्ष से अधिक आयु के 71.8 करोड़ ऐसे युवा है जिनमें 15 करोड़ के पास कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है रोजगार चाहने वालों में सबसे अधिक 2.5 करोड़ वो युवा हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा उच्चतर स्तर पर प्राप्त की है। 17 प्रतिशत आबादी तकनीकी उपाधि प्राप्त बेरोजगार है। शासन स्तर पर रोजगार के आंकड़ों पर दृष्टिपात डालें तो स्पष्ट होता है कि म.प्र. में ही लगभग 7.55 लाख कर्मचारी कार्यरत है जिनमें शासकीय विभागों में 4.46 लाख सार्वजनिक एवं अर्द्धसरकारी संस्थानों में 75 लाख, ग्रामीण निकायों में 1.68 लाख कर्मचारी सेवारत हैं।

ये आंकड़ें स्वयं बयान कर रहे है कि सभी को रोजगार, सेवा क्षेत्र में उपलब्ध कराना किसी की सरकार के वश में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार के अवसर तलाशे जायें।

सरकार ने रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की है जिनमें महत्वपूर्ण कतिपय योजनायें है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में क्रियान्वित की गई जिससे ग्रामीण गरीब लोगों को 90 से 100 दिनों तक रोजगार प्रदाय करना लक्ष्य रखा गया। 1993 में सुनिश्चित रोजगार योजना क्रियान्वित की गई जिसका लाभ कृषि कार्य के बाद के समय ग्रामीण जनमानस को रोजगार प्रदाय करना था। इन दोनों योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया गया। 2001 में इन योजनाओं का विलय समग्र ग्रामीण रोजगार योजना में किया गया। वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्रियान्वित की गई जिसमें दस लाख शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए और 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। ये दोनों योजनायें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा आरंभ की गयी। वर्ष 2008 में इनका विलय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कर दिया गया। 1997 एवं 1999 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी एवं ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई, जो ग्रामीण एवं शहरी गरीबी उपक्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। 2004 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत के सबसे पिछड़े 150 जिलों में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2006 में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों के कार्य की गारंटी हेतु कार्य कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये दोनों योजनायें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गयी। 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पारंपरिक कारीगरों, ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को स्थायी रोजगार हेतु आरंभ किया गया है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी क्षेत्रों के कुशल मजदूरी के रूप में प्रारंभ किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ करना महत्वाकांक्षी काम था।

**निष्कर्ष -**

समूची दुनिया में भारत आज अग्रणी राष्ट्रों में गिना जा रहा है। निसंदेह एवं निर्विवाद रूप से चाहे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें चाहे, भौतिक संसाधनों की हमने विश्व मानचित्र पर स्वयं को रेखांकित कर लिया है। यहां यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि आज भारत में मानवीय संसाधनों के समुचित समायोजन हेतु शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वे सराहनीय है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आज भारतीय युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास की दिशा में प्रेरित किया जाये।

**सन्दर्भ -**

1. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिकेशन, मुबंई, 2018
2. रूद्रदत एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चाँद कंपनी, दिल्ली, 2019
3. अग्रवाल एए. एच., भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्यभवन पब्लिकेशन आगरा 2015
4. मामोरिया, चतुर्भज भारत का भूगोल 2008
5. कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली 2017